

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | बुधवार, 29 नवंबर 2023

## डीडीए की दूसरे फेज की स्कीम 30 नवंबर को होगी लॉन्च पहली बार ई-ऑक्शन में बिकेंगे DDA के पेंटहाउस और फ्लैट

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डीडीए अब काफी नए तरीके आजमा रहा है। इस बार वह दूसरे चरण में शामिल 2000 से अधिक फ्लैट का ई-ऑक्शन करेगा। 30 नवंबर से यह स्कीम लॉन्च होगी। इस स्कीम में द्वारका सेक्टर-19 बी के बने डीडीए कॉम्प्लेक्स में 14 पेंटहाउस, 170 सुपर एचआईजी और 946 एचआईजी फ्लैट्स शामिल हैं। इसके अलावा इसी स्कीम में द्वारका सेक्टर-14 में बने 316 एमआईजी और लोकनायकपुरम में बने 647 एमआईजी फ्लैट्स भी शामिल हैं। इस ऑक्शन में शामिल होने के लिए लोगों को ईएमडी (अनैस्ट मनी डिपॉजिट) के तहत 10 लाख से 25 लाख रुपये जमा करवाने होंगे।

डीडीए के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ईएमडी जमा करने की प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होगी और यह 29 दिसंबर को शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 5 जनवरी 2024 से ऑनलाइन ई-ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फ्लैट के हिसाब से इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोग स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2500 रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए आवेदक को अपने फ्लैट के अनुरूप ऑनलाइन ही ईएमडी जमा करवानी होगी। यह ईएमडी फ्लैट की पेमेंट में शामिल हो जाएगी। असफल बोलीदाताओं को 30 दिन में ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ई-बिड पूरी होने के बाद आवेदक उससे पीछे नहीं हट सकेगा। यदि वह ऐसा करता है, तो उसकी ईएमडी जमा हो जाएगी। पेंटहाउस के लिए बोली दो लाख के गुणा में, सुपर एचआईजी के लिए डेढ़ लाख, एचआईजी के लिए एक लाख और एमआईजी के लिए 50 हजार के गुणा में वैलिड होगी। डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जारी होने के 60 दिनों के अंदर आवेदक को फ्लैट की कीमत देनी होगी। इसके बाद 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आवेदक को मिल सकता है। लेकिन इसमें अलॉट्टी को 10 प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा। स्केम चलने के दौरान लोग साइटों पर जाकर सैपल फ्लैट देख सकते हैं। यहां उनके लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डीडीए के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो उन्हें फ्लैट्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

### कहां, कितने फ्लैट और कितनी है उनकी कीमतें

लोकेशन	फ्लैट	एरिया	रिजर्व प्राइस	अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए तरीके आजमा रहा है DDA
द्वारका-19बी पेंटहाउस	14	424.767 वर्ग मीटर	₹5.01 करोड़	
द्वारका-19बी सुपर एचआईजी	170	211.657 वर्ग मीटर	₹2.50 करोड़	
द्वारका-19बी एचआईजी	946	171.5 से 186.09 वर्ग मीटर	₹2.02-₹2.19 करोड़	
द्वारका-14बी एमआईजी	316	116.27 से 132.35 वर्ग मीटर	₹1.25-₹1.42 करोड़	
लोकनायकपुरम एमआईजी	647	134.259 से 140.455 वर्ग मीटर	₹1.15-₹1.20 करोड़	

### इतनी ईएमडी जमा करवानी होगी

एमआईजी (2BHK)	₹10 लाख
एचआईजी (3BHK)	₹15 लाख
सुपर एचआईजी (4BHK)	₹20 लाख
पेंटहाउस (5BHK)	₹25 लाख



■ डीडीए को उम्मीद है कि ई-ऑक्शन से उसे 20-30% तक अधिक कीमत मिल सकती है।

■ 18 साल से ऊपर के लोग डीडीए की इस ई-ऑक्शन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं।

### कब क्या होगा

- 28 नवंबर: ई-ऑक्शन के लिए हेल्पडेस्क
- 30 नवंबर: रजिस्ट्रेशन शुरू, ईएमडी जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू
- 29 दिसंबर: रजिस्ट्रेशन और ईएमडी जमा करने की लास्ट डेट (शाम 6 बजे तक)
- 5 जनवरी 2024: ऑनलाइन ई-ऑक्शन कब से शुरू होगा, बाद में जारी होगा शेड्यूल



समाजिक खबरों के अंदर की बात

### क्या DDA अपने घाटे को प्रॉफिट में बदल पाएगा?

डीडीए ने सुपर लज्जरी फ्लैट में रेवेन्यू कमाने का एक मौका देखा है। पहली बार इन फ्लैट्स के लिए ई-ऑक्शन किया जा रहा है। दरअसल डीडीए के फ्लैट्स तबे समय से बिक नहीं रहे हैं। इसकी वजह से डीडीए की आर्थिक हालत भी कमजोर हो रही है। 2022 में एलजी बी. के. सक्सेना ने ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान डीडीए की आमदनी 3,578.69 करोड़ की है। वहीं कुल खर्च 6,787.83 करोड़ का है। यानी डीडीए 3209.14

करोड़ के घाटे में है। इतना ही नहीं 2016-17 से 2021-22 के दौरान डीडीए पर 8915 करोड़ की लोन देनवरी भी है। ट्वीट में लिखा गया कि डीडीए राजधानी के सबसे महंगे और बड़े रियल एस्टेट का मालिक है, लेकिन कुप्रबंधन की वजह से उसके आर्थिक हालात खराब हो गए हैं। इसके बाद से डीडीए ने फ्लैट्स का बैकलॉग क्लीयर करने के लिए कई नए तरीके अपनाए हैं। इनमें डीडीए को कुछ सफलता भी मिली है। हाल ही में डीडीए ने फ्लैट्स की मांग बढ़ाने के लिए कसलटेट भी रखा है। जो डीडीए को हाउसिंग स्कीम को सफल बनाने का एजेंडा था।



# 8 दिन की अफरातफरी खत्म, रजिस्ट्री पर रेरा ने दी राहत

**रेरा ने मंगलवार शाम वापस लिया 19 सितंबर को जारी अपना फैसला**

**एक से दो दिन में फिर से शुरू होगी रजिस्ट्री, पिछले 8 दिनों से थी बंद**

**लोगों में था डर, दिल्ली के करीब 50 प्रतिशत प्लेटों में टूट रहे हैं नियम**

**हजारों रीडर्स ने एनबीटी को भेजे सवाल, एक्सपर्ट्स ने दिए जवाब**

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में रेरा के नए आदेशों के बाद मंचे कन्व्यूजन्स के बाद मंगलवार को इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा मोड़ आया। रेरा दिल्ली में 19 सितंबर को जारी अपने यह आदेश तुरंत प्रभाव से वापस ले लिए हैं। जल्द ही रेरा इस संदर्भ में एक नया आदेश जारी करेगा। रेरा चेयरमैन आनंद कुमार ने इसकी पुष्टि की। NBT ने रेरा जारी किए गए नए आदेश के बाद लगातार मुहिम चलाई थी। इसके लिए हमने दिल्ली के लोगों से रजिस्ट्री संबंधी किसी भी जानकारी को हल करने के लिए सवाल लिए थे। हमारे पास लगातार लोगों के काफी सवाल आए। हमने इन सवालों का जवाब एक्सपर्ट्स से लेकर लोगों के कन्व्यूजन्स को बहुत हद तक दूर भी किया।

बहरहाल, रेरा चेयरमैन आनंद कुमार ने NBT को बताया कि रेरा पब्लिक के हितों के लिए काम करते हैं। साथ ही वह नियमों के मुताबिक ही काम करते हैं। इन आदेशों के बाद लोगों व विधायकों ने इसे अपने अपने तरीके से लेना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से पब्लिक को काफी अधिक परेशानी हो रही थी। इसी वजह से इन आदेशों को वापस लिया गया है। जल्द ही इसे लेकर एक नए आदेश जारी किए जाएंगे। इससे पूर्व मंगलवार को एलजी वी के सक्सेना ने राज निवास में रेरा चेयरमैन व अधिकारियों के साथ एक वार्ता की। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव व डिविजनल कमिश्नर भी शामिल हुए। एलजी ने बताया कि आदेशों के साथ से संसद, विधायक, पार्ले के साथ लोग उनसे काफी शिकायतें कर रहे हैं। मुख्य सचिव व डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि इन आदेशों की वजह से सेल डीड की रजिस्ट्री करवाने में लोगों को काफी अधिक परेशानियां आ रही हैं।

रेरा के इन आदेशों के बाद 20 नवंबर से ही दिल्ली के सभी सब डिविजनल ऑफिसों में रजिस्ट्रियों के लिए रेरा आदेशों के तहत लोगों से नक़्को मांगे जा रहे थे। नक्शा नहीं होने की वजह से उनका काम रुक हुआ था। अधिकारियों के अनुसार इन आदेशों की वजह से राजधानी की करीब 50 से 70 प्रतिशत बिल्डिंग में जल्दत से अधिक प्लेट बने थे। इसके बाद से ही लोगों में हड़कंप मच गया। उन्हें अपने मकानों को लेकर डर था। NBT 21 नवंबर से ही इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है। एनबीटी ने लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए एक एक्सपर्ट पैनाल भी बनाया था। इस एक्सपर्ट पैनाल में डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए के जैन और स्कूल



ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डीन प्रफेसर पी एस एन राय शामिल थे। वहीं लोगों के सवाल के लिए हेल्पलाइन जारी की। एक्सपर्ट्स ने उनके जवाब जवाब दिए। दरअसल राजधानी में लोगों ने 200 गज की जगह में 20 फ्लैट तक बनाए हुए हैं। इन आदेशों के पीछे रेरा ने तर्क दिया था कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि साल 2008 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। उनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आए कुछ प्रोजेक्ट में उन्हें यह खामियां मिली थीं। जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि बिल्डर नक़्को में तो मानकों के अनुरूप फ्लैट दिखाते हैं। बाद में फ्लैट बेचने समय वह स्टोर आदि की जगह किरचन बनाकर पूरा फ्लैट की शकल दे देते हैं और उसे लोगों को बेच देते हैं। दिल्ली रेरा ने एमसीडी, दिल्ली कैट बोर्ड, एनडीएमसी, डीडीए को यह निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर फ्लैट को एक नंबर देने की बात थी। रेरा को प्रेरक केनारा, पंजाबी बाग, पंचशील, उत्तम नगर आदि में इस तरह की शिकायतें

व खामियां मिली थीं। इन आदेशों के बाद लोग जहां अपनी जमीन में बने फ्लैट्स को लेकर डरे हुए थे वहां जो लोग अपनी जमीन पर फ्लैट बनाने की तैयारियां कर चुके थे वह भी डर गए थे। बिल्डर लॉबी में इन आदेशों की वजह से काफी अधिक शोर था। इसकी वजह से दिल्ली का प्रॉपर्टी बाजार भी कई दिनों तक धमका रहा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त लगभग रुक गई थी। लोगों ने NBT से जो सवाल पूछे उसमें कई ऐसे थे कि वह उक्त प्रॉपर्टी को डील कर चुके हैं, अब उन्हें इसे खरीदना चाहिए या नहीं। लोगों के जहन में यह सवाल भी थे कि वह अपने प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे या नहीं। अब देखना यह होगा कि रेरा के आदेशों के बाद रजिस्ट्री काज से शुरू होती है। अधिकारियों के अनुसार बुधवार या गुरुवार से सभी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रियां शुरू हो सकती हैं। दिल्ली में कुल 29 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं। इन सभी में सेल डीड की रजिस्ट्री का काम लगभग रुक सा गया था। 2021 में राजधानी में 1.1 लाख सेल डीड और 2022 में 1.26 लाख सेल डीड हुईं थीं। करीब एक नंबर देने की बात थी। रेरा को प्रेरक केनारा, पंजाबी बाग, पंचशील, उत्तम नगर आदि में इस तरह की शिकायतें



NBT ने लोगों से रजिस्ट्री संबंधी किसी भी जानकारी को हल करने के लिए सवाल लिए थे। हमारे पास लगातार लोगों के काफी सवाल आए। हमने इन सवालों का जवाब एक्सपर्ट्स से लेकर लोगों के कन्व्यूजन्स को बहुत हद तक दूर भी किया

■ रेरा के आदेशों के बाद 20 नवंबर से ही दिल्ली के सभी सब डिविजनल ऑफिसों में रजिस्ट्री के लिए रेरा आदेशों के तहत लोगों से नक्को मांगे जा रहे थे

■ नक्शा नहीं होने की वजह से लोगों का काम रुका हुआ था

■ रेरा ने तर्क दिया था कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि साल 2008 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए

## रेरा अधिकारियों से मिलकर एलजी ने की थी अपील

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली रेरा ने सुप्रीम कोर्ट के 2008 के नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद से लोग घर और जमीन को रजिस्ट्री को लेकर भारी कन्व्यूजन्स में हैं। मंगलवार को एलजी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए रेरा चेयरमैन और अधिकारियों के साथ मॉर्टिंग की और रेरा को आदेशों पर दोबारा से विचार करने का अनुरोध किया। एलजी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार एलजी वी के सक्सेना के पास इन आदेशों के बाद कई शिकायतें आ रही थीं। दिल्ली के एमपी, एमएलए, पार्ले, सिविल सेसपटी ऑर्गनाइजेशन के अलावा आम लोग भी काफी संख्या में उनसे इसे लेकर शिकायतें कर रहे हैं। 19 सितंबर को रेरा के नए आदेश आए थे। जिसमें सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2008 के आदेशों पर अमल करने के लिए कहा गया था। इसी को लेकर एलजी ने मंगलवार को रेरा के चेयरमैन और सदस्यों के साथ राज निवास में मॉर्टिंग की। इस मॉर्टिंग में दिल्ली के चैफ सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि लोग इसकी वजह से काफी परेशानी झेल रहे हैं। इसके बाद एलजी ने रेरा अधिकारियों से इन आदेशों पर दोबारा विचार करने की अपील की है। इस बीच दिल्ली बंगेज ने अधिसूचना वापस लेने के एलजी को धन्यवाद दिया है।



## अब भी बाकी हैं सवाल

क्या यह आदेश सुप्रीम कोर्ट 2008 के आदेशों और भारत प्लान 2021 में शामिल है? इसलिए एक्सपर्ट्स यह भी सवाल उठा रहे हैं कि भले रेरा अपने आदेशों को वापस ले ले, लेकिन यह आदेश तो पहले से ही लागू है। भारत प्लान 2007 में नोटिफाई हुआ था। उसमें भी यह नियम शामिल है। इसलिए इन पर अमल होना जरूरी है। विभिन्न एक्सपर्ट्स के अनुसार राजधानी में घरों की बढ़ती संख्या को रोकना जरूरी हो गया है। पानी, फार्म, सीकर सिस्टम न होने की वजह से यहां लोगों की लाइफस्टाइल दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अप्रूव कॉलोनियों तक में हरियाली नहीं है। यहां पौधरोपण की जगह तक नहीं है। ऐसे में यदि राजधानी का विस्तार इसी तरह होता रहता तो स्थिति और विपन्न हो जाएगी। इस वजह से पश्चिम और सड़कों पर जाम की समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है। यह अभी बढ़ती जा रही है।

## बिल्डरों को राहत

बिल्डरों के अनुसार राजधानी में लोगों को अप्रैडबल हाउस उपलब्ध करवाने का यही एक रास्ता है। लोग यहां सस्ते घरों की चाहत रखते हैं। सरकार भी अप्रैडबल हाउसिंग को बढ़ावा दे रही है। बिल्डर अब तक से ही लागू है। भारत प्लान 2007 में थोड़े अधिक फ्लैट बनाकर लोगों को 14 से 30 लाख रुपये तक में फ्लैट उपलब्ध कराए रहे हैं। यदि यह आदेश लागू रहता और इन नियमों के मुताबिक फ्लैट बनाए जाते तो फ्लैट की कीमत इन कॉलोनियों में भी 30 से 70 लाख तक होगी। यह लोकअर मीडल क्लास के लिए काफी मुश्किल है। इसलिए नियमों को वापस लेने से घरों का सपना सजने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी है। दूसरी तरफ, अफरों की मानें तो दिल्ली में 50 से 70 प्रतिशत बिल्डिंग ऐसे हैं जिनमें जरूरत से ज्यादा फ्लैट बने थे। ऐसे में इस आदेश के बाद हड़कप मचना लाजिमी था। लेकिन, अब लोगों ने भी राहत की सास ली होगी।





# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- नई दिल्ली, 29 नवंबर, 2023 दैनिक जागरण (TED)-----

## संकल्प यात्रा देश के समावेशी विकास के लिए सार्थक प्रयास : एलजी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखाकर राजधानी में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्तर पर इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी से की थी। खजूरी खास में आयोजित उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों व जनता को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आइईसी) वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए डीडीए, बैंकों, डाक विभाग, यूआइडीएआइ, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा डाक विभाग के कियोस्क भी लगाए गए थे।

उपराज्यपाल ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करते हुए विकसित भारत के सपने को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छता, रोजगार सृजन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न



खजूरी खास में दैन को हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना व साथ में मौजूद सांसद डा. हर्षवर्धन व मनोज तिवारी • जागरण

योजना जैसी अन्य कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि संकल्प यात्रा का लक्ष्य इन योजनाओं के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकांश जनता विशेषकर कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों का जनकल्याण करना है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान शहरी निकाय, जिला प्रशासन, संबंधित मंत्रालय व संबंधित विभागों द्वारा आन-स्पाट शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सभी शहरी निकायों में पीएम व एसवीए निधि और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। वहीं जिला अधिकारी कार्यालयों में आधार शिविर लगेगे। एलपीजी वितरण कंपनियों पीएम-उज्ज्वला शिविर लगाएंगी। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विकास विकल्प नहीं है, यह संकल्प है। इस मौके पर

## भारत विकसित राष्ट्र की दहलीज पर रख चुका है कदम : बिधूड़ी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयास से भारत विकसित राष्ट्र की दहलीज पर कदम रख चुका है। इस दिशा में हम तेजी से अग्रसर हैं।

सांसद ने कहा सौभाग्य की बात है कि संपूर्ण दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा खजूरी खास से शुभारंभ होने के बाद दूसरे स्थान पर ओखला फेस एक के इंदिरा कल्याण विहार के रामलीला मैदान पहुंची। यहां पर मंगलवार को सांसद ने यात्रा का स्वागत किया।

केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व उनका लाभ पहुंचाने के लिए मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खजूरी खास से किया। फिर यह यात्रा दोपहर 2.30 बजे ओखला फेस एक इंदिरा कल्याण विहार के रामलीला मैदान पहुंची।

यहां पर सांसद रमेश

बिधूड़ी ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान सांसद रमेश बिधूड़ी नेतृत्व में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के शिविर आयोजित किए गए।

इनमें पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी-पटरी वाले छोटी सड़क विक्रेताओं के लिए लोन, स्वास्थ्य जांच, कुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण आहार वितरित सहित अन्य कैंप शामिल रहे।

सांसद ने तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए हरकेश नगर और तेखंड में बरात घरों का निर्माण कराया गया।

इसके अलावा सरिता विहार अंडरपास के कार्य को पूरा कराया गया। इससे दक्षिणी दिल्ली से नोएडा जाना आसान हुआ। इस दौरान दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी, जिला महामंत्री व संयोजक विकसित भारत संकल्प यात्रा बलबीर सिंह, जिला उपायुक्त दक्षिण-पूर्व ईशा खोसला, निगम उपायुक्त मध्य क्षेत्र नवीन अग्रवाल मौजूद रहे।



रमेश बिधूड़ी •

### संकल्प यात्रा का उद्देश्य

- 1- वित्तों तक लाभ पहुंचाना - उन कमजोर व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है।
- 2- योजनाओं के बारे में जानकारी और जागरूकता पैदा करना।
- 3- नागरिकों से सीखना-व्यक्तिगत कहानियों व अनुभवों को साझा करके सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करना।
- 4- यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से सभापित लाभार्थियों का नामांकन।

सांसद डा. हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश साहिब सिंह, डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाषी पांडा, विधायक अजय महावर, मोहन सिंह बिष्ट व डीडीए के पदाधिकारी मौजूद रहे।



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण

नई दिल्ली, 29 नवंबर, 2023

NAME OF NEWSPAPERS

## आवासीय यूनिटों पर रेरा का आदेश वापस आदेश में कहा था, प्लॉट के किसी भी प्लॉट पर तय संख्या में ही कमरे बनाए जा सकेंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना की ओर से रेरा अध्यक्ष से भवन निर्माण से संबंधित नए आदेश पर दोबारा विचार करने के अनुरोध के कुछ ही घंटों बाद रेरा ने अपना आदेश वापस ले लिया। रेरा सचिव सतीश कुमार छिकारा की ओर से मंगलवार की देर शाम पुराने आदेश की वापसी का नया आदेश भी लिखित रूप से जारी किया गया।

राजनिवास के मुताबिक रेरा की ओर से 19 सितंबर को जारी आदेश को लेकर एलजी को तमाम स्तर पर प्रतिवेदन और शिकायतें मिल रही थीं। इसमें सांसदों, विधायकों, नगर निगम पार्षदों से लेकर नागरिक संगठनों और आम लोगों तक की शिकायतें भी शामिल हैं। इसमें रेरा के आदेश के बाद संपत्ति की खरीद-फरोख्त में आ रहे परेशानियों के बारे में एलजी को अवगत कराया करते हुए

• एलजी ने रेरा अध्यक्ष के साथ मुलाकात में दिल्ली के लोगों को आ रही समस्याओं को रखा था

• रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सचिव की ओर से मंगलवार को जारी किया गया आदेश

मैंने पिछले सप्ताह दिल्ली के रेरा की सितंबर 2023 की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की थी। यह खेदजनक है कि पिछले 10 दिनों के दौरान जब दिल्लीवासियों को संपत्ति पंजीकरण पर प्रतिबंध के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब अरविंद केजरीवाल सरकार ने जनता के आक्रोश पर ध्यान नहीं दिया, यह दर्शाता है कि वह जनता की भावनाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील है। इस मामले में हस्तक्षेप कर लोगों को राहत देने के लिए मैं उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आभार जताता हूँ।

—वीरेंद्र सचदेवा, अध्यक्ष दिल्ली भाजपा

समाधान की मांग की गई थी। इसी के मद्देनजर एलजी ने मंगलवार को रेरा अध्यक्ष और सदस्यों के साथ राजनिवास में मुलाकात की। इस दौरान मुख्य सचिव नरेश कुमार और मंडलायुक्त अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। एलजी ने इस बैठक में

### कितने बड़े प्लॉट पर कितनी आवासीय यूनिट तय की थीं

प्लॉट आकार (वर्ग मीटर)	आवासीय यूनिट
50 तक	तीन
51-100	चार
101-250	चार
251-750	पांच
751-1000	सात
1001-1500	सात
1501-2250	दस
2251-3000	दस

दिल्लीवासियों के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी दी और आदेश के नतीजों पर व्यापक चर्चा की। गौरतलब है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने 19 सितंबर को आदेश जारी किया था कि किसी प्लॉट के किसी भी प्लॉट

पर तय संख्या में ही कमरे बनाए जा सकेंगे। आदेश में 50 वर्ग मीटर से लेकर 3750 या इससे भी बड़े आकार के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय कर दी गई।

आदेश में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2008 के एक आर्डर का हवाला भी दिया गया है और उसी के अनुसार अलग-अलग आकार के प्लॉट पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय करने की बात कही गई।

रेरा ने दिल्ली कैंट बोर्ड, एमसीडी और डीडीए को भी इस संबंध में पत्र लिखा और आदेश के अनुसार ही बिल्डिंग प्लान जारी करने के लिए कहा। सभी सब-रजिस्ट्रार को भी रेरा ने पत्र लिखकर कहा कि 15 सितंबर के बाद किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन उक्त आदेश अनुसार आवासीय इकाइयों को चेक कर ही किया जाए। प्लॉट के आकार से अधिक आवासीय इकाइयां हैं, तो ऐसी संपत्ति का पंजीकरण नहीं किया जाए।

उचित निर्णय » संपादकीय

## डीडीए प्रीमियम आवासीय योजना में होगा पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: डीडीए की नई और अभी तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होगी। इस चरण में कुल 1100 लग्जरी फ्लैट उपलब्ध होंगे। इसमें फ्लैट ई-नीलामी के जरिये ही आवंटित होंगे। अधिकारियों के मुताबिक ई-नीलामी वाले फ्लैटों में एमआइजी, एचआइजी, सुपर एचआइजी और पेंट हाउस शामिल हैं। इनमें द्वारका सेक्टर-19 बी में बने पेंटहाउस, एचआइजी, सुपर एचआइजी शामिल हैं। इनमें से कई फ्लैटों से गोल्फ व्यू भी मिलेगा। द्वारका सेक्टर-14 में 316 एमआइजी एवं लोक नायक पुरम में 647 एमआइजी फ्लैट्स भी योजना का हिस्सा होंगे।

WWW.INDIANEXPRESS.COM

WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023

## RERA withdraws order banning registration of new property violating building norms

EXPRESS NEWS SERVICE  
NEW DELHI, NOVEMBER 28

THE REAL Estate Regulatory Authority has decided to withdraw its September order directing all sub-registrars in Delhi not to register any new property that does not conform to the Unified Building Bye Laws, 2016. Satish Kumar Chhikara, secretary, RERA, said on Tuesday. An order in this regard has been issued by RERA.

The development comes hours after L-G Vinai Kumar Saxena held a meeting at Raj

Niwas asking RERA and other officers concerned to review the order in light of complaints from several people who said they were facing problems in getting their land and flats registered following the RERA order.

The RERA had issued the said order on September 9.

Officials from L-G House said that over the past several days, Saxena has been receiving several complaints from public representatives, including MPs, MLAs and municipal councillors, along with Civil Society organisations regarding the registration of plots, flats

and sale deeds, sale and purchase allegedly coming to a halt after the RERA order. Notably, with registration process at all the sub-registrar offices practically coming to a stop for the last one week, revenue districts have only been registering DDA flats, plots, wills (wasayat nama), rent agreements.

"Registration of land and sale deeds is one of the main sources of revenue collection for the government. Its not only creating problems for public, especially middle- and lower-income groups, but for the government exchequer as well," an official said.



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI  
WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023

## NAME OF NEWSPAPERS ----- DATED ----- RERA withdraws September order that stalled property registrations in capital

TIMES NEWS NETWORK

**New Delhi:** The Real Estate Regulatory Authority of Delhi has withdrawn its September 11 order that directed the sub-registrars in the national capital not to register the sale deeds of properties that contravened the building byelaws.

"Considering the various facts on record, the Authority has decided to withdraw its order of September 11, 2023 with immediate effect," the order issued by RERA secretary Satisch Kumar Chhikara read.

The fresh order came hours after lieutenant governor VK Saxena held a meeting with RERA chairman and members to discuss the hardship faced by Delhiites due to the restrictions imposed by the order and impressed upon them to revisit the directions.

"The LG in the past one week received several representations and complaints from public representatives — MPs, MLAs and municipal councillors — civil society organisa-

### RAJ NIWAS OFFICIAL SAYS

**The LG in the past one week received several representations and complaints from public representatives, civil society organisations and general public about the problems being faced after the recent order of RERA regarding registration of sale deeds for properties being sold and bought**

tions and general public about the problems being faced by people after the recent order of RERA regarding registration of sale deeds for properties being sold and bought," said a Raj Niwas official.

"The LG today met the chairman and members of RERA along with the chief secretary and the divisional commissioner at Raj Niwas. He brought to their notice the acute problems and harassment being faced by the residents of Delhi and had wide ranging discussions regarding the repercussion of the said order. The LG impressed upon and requested the RERA to accordingly re-

visit the said order in view of the hardship it is causing to common people in Delhi," the official added.

In its September 11 order, which was received by sub-registrars of Delhi on November 17, RERA directed that the sale deed of properties that contravened the maximum number of dwelling units permitted on a certain plot size under the Unified Building Bye Laws for Delhi, 2016 (UBBL) should not be registered henceforth.

RERA also asked the civic bodies not to clear building plans that had more than the permissible number of dwell-

ing units mandated by UBBL according to the plot size. RERA's order said that all building plans sanctioned by Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council, Delhi Cantonment and Delhi Development Authority after September 15 should clearly indicate the total number of dwelling units being constructed and the number of dwelling units on each floor.

The order, said officials, had an immediate impact on sale and purchase of built-up properties in unauthorised, regularised, and planned localities. The 29 sub-registrars and joint sub-registrars refused to accept sale deeds from buyers for their registration and sought clarity from the divisional commissioner on the issue.

Though the order largely affected the transaction of builder flats and floors, sources said the registration of sale deeds of all kinds of properties came to a screeching halt after the RERA order.

हिन्दुस्तान

## एलजी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

एलजी ने विशेष रूप से डिजाइन की गई पांच आईईसी (सूचना, शिक्षा व संचार वेन को रवाना किया। यह दिल्ली के 11 जिलों में 600 से अधिक जगहों से गुजरेगी। यात्रा के दौरान पीएम स्वनिधि, मुद्रा ऋण, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल भुगतान क्रांति, पीएम ई-बस सेवा, आयुष्मान भारत, पीएम आवास

(शहरी), पीएम उज्वला योजना जैसी केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी।

यात्रा के उद्घाटन समारोह अवसर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, चांदनी चौक के सांसद हर्षवर्धन, पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधुड़ी, करावल नगर के विधायक मोहन सिंह बिट्ट, घोडा से विधायक अजय महावर उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, डीडीए उपाध्यक्ष सुभाषीष पन्डा और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती उपस्थित रहे।



उपराज्यपाल ने मंगलवार को खजूरी खास में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। • पेट



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

हि हिन्दुस्तान

DE NIA/SDADEDS

DATED

## 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सभी श्रेणी के आवासों के लिए 11 दिसंबर से बुकिंग शुरू डीडीए फ्लैटों के लिए चार हजार पंजीकरण

### योजना

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई आवासीय योजना में अब तक चार हजार से अधिक आवेदनकर्ताओं ने पंजीकरण करा लिया है। द्वारका, लोकनायक पुरम और नरेला में 30 हजार से अधिक फ्लैट के लिए 24 नवंबर को पंजीकरण शुरू हुआ था।

आवेदनकर्ता ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी व एचआईजी फ्लैटों के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर इन सभी श्रेणी के फ्लैटों के लिए 11 दिसंबर से बुकिंग शुरू होगी। आवेदनकर्ता अपनी प्राथमिकता के अनुसार फ्लैटों को बुक कर सकेंगे। इनमें ईडब्ल्यूएस के लिए 50 हजार रुपये, एलआईजी के लिए 1 लाख रुपये, एमआईजी के लिए 4 लाख रुपये और एचआईजी के लिए 10 लाख रुपये बुकिंग शुल्क देना होगा।

बुकिंग प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी: डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फ्लैटों की पंजीकरण और बुकिंग प्रक्रिया 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। आवेदनकर्ताओं को फ्लैटों से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी फ्लैटों की जगहों पर तैनात किए गए हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों के नंबर भी योजना से जुड़े ब्रोशर में उपलब्ध हैं। इन पर कॉल करके लोगों को फ्लैटों के संबंध में सभी तरह की जानकारी मिलेगी।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव से बदल रहा है नजरिया: नरेला के विभिन्न श्रेणी में हजारों फ्लैट

24 नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोगों में खास उत्साह

30 हजार से अधिक आवास नरेला, द्वारका, लोकनायक पुरम में आवंटित होंगे

### निवेश के लिहाज से जोर दे रहे लोग

डीडीए ने नरेला के विभिन्न सेक्टरों में तीन कमरों के एचआईजी के कुल 1,184 फ्लैट, दो कमरों के एमआईजी के कुल 1,976 फ्लैट, एक कमरे के एलआईजी के कुल 19,680 फ्लैट योजना में शामिल किए हैं। हालांकि, फ्लैटों का पंजीकरण कराने वाले आवेदनकर्ताओं की प्राथमिकता अब इन फ्लैटों को निवेश के लिहाज से खरीदने की है। इस संबंध में नरेला में फ्लैट देखने आ रहे लोगों ने फ्लैट की बुकिंग प्रक्रिया में शामिल होने की दिलचस्पी सिर्फ निवेश के तौर पर ही दिखाई है।



### रेट पर विश्लेषण के लिए कंसलटेंट से बातचीत

डीडीए ने दिल्ली-एनसीआर में मौजूद विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के रेट पर विश्लेषण करने के लिए एक कंसलटेंट नियुक्त किया है। इस कंसलटेंट से डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। एनसीआर के शहरों में मौजूद फ्लैटों में मिलने वाली सुविधाओं पर कंसलटेंट ने रिपोर्ट तैयार की है। डीडीए इस रिपोर्ट पर अब अध्ययन कर रहा है। इस आधार पर विभिन्न फ्लैटों की कीमतें भी निर्धारित करने की योजना पर काम चल रहा है।

योजना में शामिल हैं। इसके बाद भी यहां पर फ्लैट देखने आने वाले लोगों ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। मंगलवार को फ्लैट देखने आए राजौरी गार्डन से सुनील सिंह ने कहा कि डीडीए नरेला में हजारों फ्लैट निकाल रहा है। फ्लैट के आसपास की

सड़कों को बेहतर किया गया है। लेकिन पीतमपुरा, रोहिणी, बादली और बवाना के रास्ते से हुए जगह-जगह पर डीडीए के नरेला के फ्लैटों के बड़े बोर्ड नहीं लगे हैं। सिर्फ कुछ ही जगहों पर मौजूद हैं। यहां पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर बेहतर ढंग से ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मेट्रो के साथ

### द्वारका में 88 लाख रुपये तक नई कीमत तय

डीडीए ने एक कमरे के द्वारका सेक्टर-14 के फेज-2 स्थित एलआईजी फ्लैटों की कीमत 77 लाख से 88 लाख रुपये इस नई आवासीय योजना में निर्धारित की है। यहां पर 316 एलआईजी फ्लैट योजना में शामिल किए हैं। अब फ्लैट देखने आ रहे लोगों ने इसकी कीमत पर विचार करने के लिए कहा है। फ्लैट देखने आ रहे कई आवेदनकर्ताओं ने कहा कि द्वारका के इस सेक्टर में 88.16 से 100.02 वर्ग मीटर पर एक कमरे का एलआईजी फ्लैट 77 से 88 लाख रुपये में दिया जा रहा है, जबकि

नरेला सेक्टर-जी 2 के पॉकेट 1 से 6 में 7,913 फ्लैट का क्षेत्रफल 49.9 वर्ग मीटर है। इसकी कीमत 20.90 से 21 लाख रुपये है। साथ ही नरेला सेक्टर-जी 7 में पॉकेट 6,7 और 11 में कुल 11,767 फ्लैटों को 49.9 वर्ग मीटर में आवासीय योजना में जोड़ा गया है। इसकी कीमत 25.2 लाख रुपये है। ऐसे में द्वारका सेक्टर-14 में 88.16 से 100.02 वर्ग मीटर में दो कमरों के एमआईजी फ्लैटों का निर्माण करना चाहिए था। इस जगह पर कुछ और वर्ग मीटर शामिल करते हुए अच्छे क्षेत्रफल में दो कमरों के फ्लैटों का निर्माण किया जा सकता था।

### विभिन्न श्रेणी में 22 हजार से ज्यादा आवास शामिल, सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की मांग

नरेला के विभिन्न श्रेणी में कुल 22,840 फ्लैट योजना में शामिल हैं। इसके बाद भी यहां पर फ्लैट देखने आने वाले लोगों ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। मंगलवार को फ्लैट देखने आए राजौरी गार्डन से राजेश सिंह ने कहा कि नरेला में डीडीए हजारों फ्लैट निकाल रहा है। फ्लैट के आसपास की सड़कों को बेहतर किया गया है, लेकिन पीतमपुरा, रोहिणी, बादली और बवाना के रास्ते से हुए जगह-जगह पर डीडीए के नरेला के फ्लैटों के बड़े बोर्ड नहीं लगे हैं। सिर्फ कुछ ही जगहों पर मौजूद हैं। यहां पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर बेहतर ढंग से ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मेट्रो के साथ बस रूटों को भी बढ़ाना चाहिए। पुलिस चौकी बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए।

बस रूटों को भी बढ़ाना चाहिए। पुलिस चौकी बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए।

डीडीए ने दिल्ली-एनसीआर में मौजूद विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के रेट पर विश्लेषण करने के लिए एक कंसलटेंट नियुक्त किया है। इस कंसलटेंट से डीडीए के वरिष्ठ

अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। एनसीआर के शहरों में मौजूद फ्लैटों में मिलने वाली सुविधाओं पर कंसलटेंट ने रिपोर्ट तैयार की है। डीडीए इस रिपोर्ट पर अब अध्ययन कर रहा है। इस आधार पर विभिन्न फ्लैटों की कीमतें भी निर्धारित करने की योजना पर काम चल रहा है।

### डीडीए के कॉल सेंटर से लोन संबंधी जानकारी लें

डीडीए फ्लैटों के लिए आवेदन करने वालों को लोन से संबंधित जानकारी भी देगा। इस संबंध में डीडीए के कॉल सेंटर के नंबर 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं। डीडीए कर्मी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी जैसे फ्लैटों का पंजीकरण करने वाले को लोन के बारे में बताएंगे।



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI  
WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023

Hindustan Times

## Saxena Kicks Off Viksit Bharat Sankalp Yatra

### To Apprise Citizens Of Central Govt Schemes

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Tuesday flagged off the Viksit Bharat Sankalp Yatra in the presence of MPs and senior government officials in northeast Delhi.

The yatra, started about five months before the general elections, aims to educate people about schemes launched by the central government and how they can benefit from them.

During the Delhi campaign, which will cover over 600 locations in 11 districts, information, education and communication vans will travel to rural and urban areas to promote schemes such as the Pradhan Mantri Awas Yojana, Ujjwala Yojana, Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Svanidhi Yojana and the Garib Kalyan Yojana, among others.

"The Centre has launched many welfare schemes to reach out to the general public as well as marginalised communities under the leadership of PM Narendra Modi. To disseminate information and create awareness about these initiatives and make them beneficiaries too, the PM launched the yatra on November 15 in Jharkhand. Now, we will promote these initiatives in Delhi, hold direct dialogue with people and help them get the benefits," the LG told the crowd at Khajoori Khas.

He said camps would be organised to reach out to people in far-flung areas. "People will be able to get their Aadhaar updated and get enrolled under schemes after submitting minimum documents..." the LG said. These camps will be organised by



**FIVE MONTHS TO POLLS:** LG VK Saxena with BJP MPs Harsh Vardhan and Manoj Tiwari during the inauguration of Viksit Bharat Sankalp Yatra at Garhi Mendu village in northeast Delhi on Tuesday

urban local bodies and the district administration.

The LG, along with MPs and senior officials, took a Viksit Bharat Sankalp pledge.

"As India is aiming to become a developed country by 2047, we want the common man to know how the government functions and how they can be associated and become a part in the development process," Manoj Tiwari, the MP from northeast Delhi, said.

"This yatra is an opportunity to bring people closer to government programmes. In 2014, when Narendra Modi took the oath as PM, India's economy was in the 14th position in the world and today it has jumped to the fifth place. The objective of the yatra is to not only disseminate information but also to learn from citizens' experiences," he said.

Highlighting the development work done in northeast Delhi, Tiwari said that the elevated crossing on the Pusta Road will become operational in February. "Earlier, we did not have a single central school in northeast Delhi, but now a building has been constructed

for one school which will become operational anytime soon and permission for three more schools has been granted. We are thankful to the DDA for allocating land for the project at a subsidised rate. The Yamuna riverfront has seen major rejuvenation with the efforts of the LG, who is frequently visiting the place. We have a passport office in Yamuna Vihar and efforts are on to make a proper station at the Saboli railway halting point," he said.

At the event, organised by Delhi Development Authority, kiosks of DDA, banks, postal department, UIDAI and the Union petroleum and natural gas ministry were set up, highlighting government schemes. DDA vice-chairman Subhasish Panda said the authority was making all effort to raise awareness through outreach.

A health awareness camp, in which certificates under Sunidhi Yojana was distributed, was held. NDMC vice-chairman Satish Upadhyay said: "The government aims to enhance progress for the underprivileged."

## Delhi LG, MPs, flag off Viksit Bharat yatra

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi lieutenant governor (LG) VK Saxena on Tuesday flagged off the "Viksit Bharat Sankalp Yatra" to raise awareness about various welfare programmes launched by the Government of India, through outreach activities.

The national yatra was launched by Prime Minister Narendra Modi on November 15 from Khunti in Jharkhand on the occasion of Janjatiya Gaurav Divas, marking the birth anniversary of tribal icon Birsa Munda.

On Tuesday, Saxena was accompanied by members of Parliament (MPs) from Delhi—Harsh Vardhan (Chandni Chowk), Manoj Tiwari (North East Delhi), Ramesh Bidhuri (South Delhi) and Parvesh Verma (West Delhi)—as well as chief secretary Naresh Kumar.

Launching the yatra, the LG

said, "A number of welfare schemes, particularly those related to cleanliness, and employment generation, are being run by the Government of India. The Sankalp Yatra aims at raising awareness among the masses about these schemes and bringing maximum number of people, particularly those belonging to the weaker sections, under the ambit of these programmes."

The LG said that the camps will reach around 600 localities in the 11 districts of Delhi.

Saxena also flagged off IEC (Information, Education and Communication) vans to disseminate information about the schemes. Kiosks of Delhi Development Authority (DDA), banks, postal department, UIDAI, Union Petroleum and Natural Gas ministry and postal department were also put up, highlighting various government schemes.



LG VK Saxena with Delhi MPs Harsh Vardhan and Manoj Tiwari at the launch of the sankalp yatra on Tuesday. SANCHIT KHANNA/HT PHOTO



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी  
DELHI

नई दिल्ली | बुधवार, 29 नवंबर 2023

DATED

शुभारंभ

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी

## भारत के समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास है संकल्प यात्रा: उपराज्यपाल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करते हुए 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम है। यह बात दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खजुरी खास में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि कई कल्याणकारी स्कीम, विशेष रूप से स्वच्छता, रोजगार सृजन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसी स्कीम हैं जो भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाई जा रही हैं।

सक्सेना ने बताया कि संकल्प यात्रा का लक्ष्य इन स्कीमों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना है और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकांश जनता, विशेषकर कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों का जनकल्याण करना है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर, मैं भारत सरकार और दिल्ली सरकार की सभी एजेंसियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि वे जन कल्याण के कार्यों हेतु स्वयं को समर्पित करें तथा जनता से सीधा संवाद करें। दिल्ली के खजुरी खास इलाके से मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी)



कार्यक्रम के दौरान मंच पर एलजी वीके सक्सेना, सांसद हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, रमेश बिघूड़ी व अन्य।

वीके सक्सेना ने यात्रा का शुभारंभ हरीझंडी दिखाकर किया। इस दौरान स्थानीय सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश बिघूड़ी, प्रवेश वर्मा, डॉ. हर्षवर्धन, भाजपा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष विस मोहन सिंह बिष्ट और काफी तादाद में अन्यकार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल लोगों को उपराज्यपाल ने भारत को विकसितराष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। उपराज्यपाल सक्सेना ने यात्रा के शुभारंभ के बादकहा कि देश और दिल्ली के लोगों को इस यात्रा का लाभ मिलेगा।

### विकसित भारत संकल्प की दिलाई शपथ

एलजी ने इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं आम जनता को विकसित भारतसंकल्प की शपथ भी दिलाई और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) दैन को हरी झंडी दिखाई। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए डीडीए, बैंको, डाकविभाग, युआईडीएआई, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा डाक विभागके किरासक भी लगाए गए।

### केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है: तिवारी

वहीं, सांसद मनोज तिवारी ने कहा किप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की थी। अब इस यात्रा कीशुरुआत दिल्ली में भी हो गई। यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तकपहुंचाना है। इस कार्यक्रम के तहत सूचना वाहन, कार्यकर्ताओं के समूह के माध्यम से देशभर के लोगों कोकेंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और उनतक योजनाओं का लाभ पहुंचायाजाएगा। मनोज तिवारी ने बताया कि दिल्ली के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों से भी सूचनावाहन रवाना किया जाएगा।

### विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य

व्यक्तों तक लाभ पहुंचाना-उन कमजोर व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है। योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाना और जागरूकता पैदा करना।

नागरिकों से सीखना- व्यक्तिगत कहानियों/अनुभवों को साझा करके सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करना।

यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन।

### ऑन-स्पॉट कैंप आयोजित किए जाएंगे

पीएम-एसवीए निधि कैंप-सभी यूएलबी हैल्थ कैंप-सभी यूएलबी आधार अपडेशन कैंप-जिला कलेक्टर पीएम-उज्ज्वला कैंप-एलपीजी वितरण कूपनियां।

सरकार द्वारा उचित समय पर तय की गई कोई अन्य योजना।



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer

DATED

NEW DELHI | WEDNESDAY | NOVEMBER 29, 2023

## RERA lifts ban on registration of property after meeting LG

PTI ■ NEW DELHI

The Delhi Real Estate Regulatory Authority withdrew its September order directing sub registrars not to register properties in violation of building bylaws, hours after its top brass met Lt Governor V. K. Saxena on Tuesday, officials said.

Earlier in the day, Saxena met the chairman and members of Delhi RERA along with the chief secretary and divisional commissioner at Raj Niwas over the issue.

"The LG impressed upon and requested the RERA to revisit its order in view of the hardship it is causing to common people in Delhi," said a Raj Niwas official.

A fresh order issued by Delhi RERA secretary stated, "Considering the various facts on record, the Authority has decided to withdraw its order dated 11.09.2023 with immediate effect."

During the meeting with RERA chairman and members, the LG brought to their notice the



"acute problems and harassment" being faced by the residents of Delhi in a wide ranging discussion regarding the "repercussion of its order", the Raj Niwas official said.

The Delhi RERA had in its order on September 11 directed the sub registrars to refrain from registering additional dwelling units on a plot, constructed beyond the number of units permitted as per its size. It had also directed that all building plans sanctioned after September 15, 2023, must clearly indicate the total number of dwelling units that can be constructed on a plot with each

dwelling marked separately in the plan.

After the circulation of the Delhi RERA order, the sub registrars of revenue department stopped registration of properties, although senior government officers claimed no order to this effect was issued by the department.

The Raj Niwas official said that the LG had received representations and complaints from MPs, MLAs, municipal councillors, civil society organisations, as well as general public on the problems faced in registration of sale deeds for properties being sold and bought.

Delhi BJP president Virendra Sachdeva who had earlier raised the issue welcomed withdrawal of the RERA order saying the LG has fulfilled the hopes of Delhiites by getting it revoked. The September order of Delhi RERA had stated that as per the Unified Building Bylaws, 2016, and the Supreme Court order of March 14, 2008, the number of dwelling units was fixed to just three in case of plots measuring up to 50 square metres

and four in case of plot sizes above 50-250 square metres.

The number of dwelling units of other plot sizes measuring up to 3,750 square metres and above were also fixed in the order.

The RERA also alleged in its order that such civic authorities as MCD, DDA, NDMC, and Delhi Cantonment Board were sanctioning building plans with additional dwelling units without kitchen, or built with pantry or store.

"The builders after sanction of building plans, convert pantries and stores into kitchens and sell units as separate dwelling units, circumventing orders of the Hon'ble Supreme Court," the authority had charged in its order.

The Delhi RERA order had stated that as per the Unified Building Bylaws, 2016, and the Supreme Court order of March 14, 2008, the number of dwelling units was fixed to just three in case of plots measuring up to 50 square metre and four in case of plot sizes above 50-250 square metre.



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

29 नवम्बर • 2023

राष्ट्रीय  
सहारा

## हेल्थ एवं स्वदेशी दवा वितरण शिविर का आयोजन

नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, दिल्ली मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन, डीडीए बागवानी खंड-3 समेत कई अन्य सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में विकास पुरी स्थित गौरी शंकर छोड़ीए पार्क में गुरुपर्व कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेगा हेल्थ कैम्प और स्वदेशी दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कैम्प की चीफ बहन रेनु अरोड़ा के अनुसार घर पर तैयार की गई औषधीय गुणों की खान एलोवेरा (घृत कुमारी) के पौधों की रोपाई विशेष रूप से अरोड़ा परिवार के नाम पर तैयार क्यारी में हुई। कार्यक्रम के संयोजक रागवेंद्र शुक्ल के अनुसार पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों में यह परंपरा-सी धीरे-धीरे बनने लगी है।



उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास से मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना।  
फोटो : एसएनबी

## एलजी का रेरा से आदेश पर दोबारा विचार करने का आग्रह

नई दिल्ली (भाषा)। उप-राज्यपाल वी के सक्सेना ने प्रदेश की रिवल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) से अपने आदेश की फिर से समीक्षा करने का आग्रह किया है। इस आदेश के लागू होने के बाद शहर में संपत्तियों का पंजीकरण रुक गया है। एलजी कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सक्सेना ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मंगलवार को राज निवास में मुख्य सचिव और मंडलायुक्त के साथ दिल्ली रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की। राज निवास के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में आम लोगों को छोड़ कर पेशानी को देखते हुए उप-राज्यपाल ने रेरा से अपने आदेश पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। उप-राज्यपाल ने रेरा के आदेश पर व्यापक चर्चा में दिल्ली के निवासियों को छोड़ कर गंभीर समस्याओं और उल्टीझ को उनके संज्ञान में लाया।

दिल्ली रेरा ने 19 सितंबर को अपने आदेश में उप-राज्यपाल के निर्देश दिया था कि वे किसी भूखंड पर स्वीकृत

इकाइयों की संख्या से अधिक निर्मित अतिरिक्त आवास इकाइयों का पंजीकरण करने से बचें। इससे यह भी निर्देश दिया कि 15 सितंबर, 2023 के बाद स्वीकृत सभी भवन योजनाओं में एक भूखंड पर बनाई जा सकने वाली आवास इकाइयों की कुल संख्या को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और योजना में प्रत्येक आवास को अलग से चिह्नित किया जाना चाहिए।

रेरा के आदेश के बाद, राजस्व विभाग के उप-पंजीकों ने संपत्तियों का पंजीकरण बंद कर दिया। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया कि विभाग ने इस आशय का कोई आदेश जारी नहीं किया था। रेरा ने अपने आदेश में यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड जैसे नगरिक प्राधिकरण बिना रसीद के अतिरिक्त आवास इकाइयों के साथ या पेंटी या स्टेर के साथ निर्माण योजनाओं को मंजूरी दे रहे थे।

### इस आदेश के लागू होने के बाद शहर में संपत्तियों का पंजीकरण रुक गया

## समाज के हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना यात्रा का उद्देश्य : एलजी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी आईसी वैन के एक को रवाना किया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास से रवाना इस यात्रा के दौरान सांसद डा. हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश साहिब सिंह समेत अन्य गण्यमान्यजन मौजूद थे। दरअसल प्रधानमंत्री ने देशव्यापी स्तर पर इस यात्रा की शुरुआत झारखंड के खूंटी से की थी।

यह यात्रा राजधानी के सभी 11 जिलों से कुल 600 स्थानों से गुजरेगी। इसका उद्देश्य केंद्र की पीएम स्वनिधि, मुद्रा ऋण, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल भुगतान क्रांति, पीएम ई-बस सेवा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास (शहरी), प्रधानमंत्री

उज्ज्वला योजना समेत अन्य केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना है। यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस मौके पर उप-राज्यपाल ने

### एलजी ने झंडी दिखाकर रवाना की संकल्प यात्रा

सभी को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में योजनाओं से संबंधित विभागों डीडीए, बैंकों, डाक विभाग, यूआईडीएआई, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और डाक विभाग के क्योस्क भी लगाए थे। क्योस्क पर तैनात कर्मचारी लोगों को विस्तार के साथ योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। उप-राज्यपाल ने बताया कि सभी योजनाओं से संबंधित अलग-अलग वैन तैयार की गयी हैं।



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

WEDNESDAY, 29 NOVEMBER, 2023 | NEW DELHI

NAME OF NEWSPAPE

## L-G Saxena flags off Viksit Bharat Sankalp Yatra in Delhi

OUR CORRESPONDENT

**NEW DELHI:** Delhi Lieutenant Governor VK Saxena on Tuesday flagged off the Viksit Bharat Sankalp Yatra in the national capital from the Khajoori Khas area.

Prime Minister Narendra Modi had launched the nationwide programme from Khunti in Jharkhand to reach out to citizens who are eligible for various central schemes but have not benefitted so far.

The campaign to reach out to beneficiaries of the Centre's flagship programmes both in rural and urban areas will culminate on January 25 next year.

While addressing a gathering at the event, Saxena said this yatra is a major step towards fulfilling the dream of a "developed India" while promoting inclusive development.

Under the leadership of the prime minister, a number of welfare schemes like Swachhata, Rojgaar Sagam Yojana, Ayushman Bharat, PM Awas Yojana, PM Gareeb Kalyan Yojana etc. are being run. The



L-G VK Saxena flags off Viksit Bharat Sankalp Yatra, in New Delhi on Tuesday  
PIC/NAVEEN SHARMA

purpose of this yatra is to take these schemes to every corner of the country and connect more and more people, particularly those belonging to the weaker sections, with these schemes,' he said.

The yatra will pass through all 'gram panchayats, nagar panchayats and urban bodies,' he said.

'On this occasion, I would also urge all agencies and senior officials of the central and Delhi governments to dedicate themselves to the works of public welfare and establish

direct communication with the public,' the Lt Governor said.

He also administered a pledge - Viksit Bharat Sankalp - to all the dignitaries and people present on the occasion and flagged off IEC (Information, Education and Communication) vans to disseminate information about schemes, officials said. Kiosks of DDA, banks, postal department, UIDAI, union petroleum and natural gas ministry and postal department were also put up, highlighting various government schemes, they said.

## Delhi min slams Centre over demolition of houses in slum cluster

OUR CORRESPONDENT

**NEW DELHI:** Delhi Urban Development Minister Saurabh Bharadwaj slammed the Centre on Tuesday over the demolition of houses at a slum cluster located between the Sunder Nursery and Delhi Public School, Mathura Road.

Bharadwaj alleged that through its Land And Development Office (LNDO) department, the Bharatiya Janata Party-led Centre took a "cruel stand" in the high court to demolish the slums and that the Delhi Development Authority (DDA) was "duty-bound to rehabilitate" the poor people before their houses were demolished.

The slum cluster, inhabited by about 1,000 to 1,500 people, most of whom work as ragpickers, street hawkers, domestic helps, labourers and small-scale traders, was demolished in a drive following a court order last week. 'According to the law, the central government's DDA was duty-bound to rehabilitate these poor people before the demolition of their homes.



Saurabh Bharadwaj

'No government can be as inhuman as the Centre'

Even though the high court had provided the relief in view of the Graded Response Action Plan-3, the Centre provided special permission to demolish their homes in the winter. It is shocking that the Centre did not think about these poor families, their children and the elderly,' Bharadwaj said.

'No government can be as inhuman as the Centre. One can imagine the condition of these families, who will now have to live on the roads, without even a roof on their heads,' the Aam Aadmi Party (AAP) leader added.



**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

**LIBRARY**

**PRESS CLIPPING SERVICE**

**the pioneer**

WEDNESDAY | NOVEMBER 29, 2023

# DDA Premium Housing



Where Development  
Values Nature



Registration starts from  
**Tomorrow**



For more information,  
scan QR Code

**Penthouses, Super HIG, HIG Dwarka Sector-19 B**  
**MIG Dwarka Sector-14**  
**MIG Loknayakpuram**

**1800110332**  
**www.dda.gov.in**

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India

Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023. Follow us on: [@ddaoofficial](#) [official\\_dda](#) [official\\_dda](#) [Official\\_dda](#)

All New  
Freehold Flats

Multi-storeyed  
Equipped with lifts

STP, Park, Water Drainage  
Playground

No restriction for those  
who own house/plot in Delhi

Apply online through  
[www.dda.gov.in](http://www.dda.gov.in)

Allotment through  
auction

Designated parking  
free with each flat



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY

अमर उजाला PRESS CLIPPING SERVICE

बुधवार, 29 नवंबर 2023

## डीडीए प्रीमियम हाउसिंग



Where Development  
Values Nature

पंजीकरण  
कल  
से आरंभ



अधिक जानकारी के लिए  
कृपया कॉल करें

पेंटहाउस, सुपर एचआईजी, एचआईजी द्वारका सेक्टर-19 बी  
एमआईजी द्वारका सेक्टर-14  
एमआईजी लोकनायकपुरम

1800110332  
www.dda.gov.in

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली 110023. हमें फॉलो करें: [f @ddaofficial](#) [x official\\_dda](#) [i official\\_dda](#) [y Official\\_dda](#)

सभी नए  
प्रीहोल्ड फ्लैट

बहुमंजिला,  
लिफ्टों से सुसज्जित

एसटीपी, पार्क, जल निकासी,  
खेल का मैदान

दिल्ली में घर/प्लॉट रखने  
वालों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं

ऑनलाइन आवेदन करें  
www.dda.gov.in के माध्यम से

आबंटन नीलामी  
के माध्यम से

प्रत्येक फ्लैट के साथ  
निःशुल्क पार्किंग